नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 066
दि. 05.07.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूपी: सीएम योगी बोले- 12 वर्षों में बदल गया प्रदेश, न तो कहीं दंगा हुआ और न ही लगा कर्फ्यू ; अब यह उत्तम प्रदेश

(जीएनएस)।

लखनऊ

यूपी भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से बदलते यूपी की तस्वीर बदली है। नौ वर्ष में यूपी में न तो कोई दंगा हुआ और न ही कर्फ्यू लगा। जिस प्रदेश की छवि उपद्रव वाला था वह अब उत्सव प्रदेश बन गया है। परंपरागत उद्यम फिर से प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में सबने बदलता भारत देखा है।

पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि बंगाल में सभी राजनीतिक विश्लेषक कहते थे कि यह भाजपा के लिए अभेद्य है, लेकिन उनके सभी विश्लेषण धराशायी हुए। भाजपा ने बहुमत के साथ पहली बार बंगाल में सरकार बनाई। जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन धरा पर कमल खिला। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक थी।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि, दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के सामने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के बारे में अच्छी धारणा बनी है। भारत की बा' सुरक्षा अभेद्य हुई। अब दुश्मन भारत को आंख नहीं दिखा सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नक्सलवाद से मुक्त हुआ और आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई। योजनाओं के क्रियान्वयन को आमजन तक पहुंचाने के लिए संगठन व कार्यकताओं की भूमिका पर भी बल दिया। अब किसान की आमदनी कई गुना बढ़ी है। 2014 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 5 साल में हम यूपी में किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे। सरकार गन्ना किसानों को 400 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, निवेश, रोजगार आदि की योजनाओं पर जोर देते हुए कहा कि अभी एक साथ यूपी के अंदर 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई थी। हर जिले में 500 से लेकर 1000, 1200, 1500 तक नौजवान भर्ती हुए थे। सपा शासन में यह भर्ती असंभव थी और पारदर्शिता तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग विकास, गरीब कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था आदि मुद्दे पर डबल इंजन सरकार के सामने नहीं टिक पाते, वे जातीय विभाजन, भाजपा और विचार परिवार के बीच में मतभेद का भ्रम फैलाते हैं। हमें इससे खुद को दूर रखना है। किसी भी ऐसे मामलों में नहीं पड़ना है, जो माहौल खराब करता हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई टीम, नए तरीके से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी और सरकार व संगठन के बीच में बेहतर समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ेगी।

राष्ट्रीय अध्यक्ष सहज और सरल : पंकज चौधरी

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पार्टी कार्यालय में नितिन नवीन और बीएल संतोष का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सहज और सरल हैं, लेकिन काम से समझौता नहीं करते हैं। उनका यह स्वाभाव हमारे लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि नई टीम की घोषणा के बाद हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है।

पंकज चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन चुनावी शंखनाद की घोषणा है। इस चुनावी युद्ध में यही टीम काम करेगी। प्रदेश की टीम जिलों के साथ बेहतर समन्वय करेगी और जिले की टीम चुनावी युद्ध को बूथ स्तर तक ले जाकर मतदाताओं तक पहुंच को सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि हम सब अपने दायित्व में जरा भी शिथिल नहीं होंगे। सरकारों के बेहतर कार्यों को हमें जन-जन तक पहुंचाना है। हमें निरंतर संवाद बनाए रखना है। राजनीतिक संवाद के क्षेत्र में भाजपा से बेहतर प्रणाली किसी और पार्टी के पास है ही नहीं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें और अधिक सुधार होगा। हमारे संगठन की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं और हमें इन्हीं कार्यकताओं से निरंतर संवाद करना है। हमें मतदाता को 2012 से 2017 तक की भयावह व्यवस्था का स्मरण कराना है जो बच्चे 2017 में 10 वर्ष के थे अब वो वोटर हैं उन्हें भी समझाना है कि सपा का काल कैसा था और पिछले 9 वर्षों में सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा कि 2027 में हम 2017 से बड़ी जीत दर्ज करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में आठ जुलाई को अपने हाथों से शिक्षकों और कार्मिकों को देंगे स्वास्थ्य कार्ड

(जीएनएस)।

वाराणसी। शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कार्मिकों की बहुप्रतिक्षित मांग पूरी होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ जुलाई को वाराणसी से शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना लांच करेंगे। वह अपने हाथों 10 शिक्षकों को स्वास्थ्य कार्ड देंगे। यह सुविधा बेसिक और माध्यमिक के सभी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मियों को मिलेगा।

योगी के हाथों योजना की लांचिंग के लिए आठ जुलाई को बड़ालालपुर स्थित टीएफसी सभागार में सुबह 10 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि योजना से सभी शिक्षकों, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, रसोईया, अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक, अशंकालिक शिक्षकों को कैशलेस सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ एवं मानदेय शिक्षकों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों और उनके परिवार के सदस्य लाभार्थी होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री बच्चों के लिए बैग, ड्रेस के लिए 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से जारी करेंगे।

आयोजन के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी सात जुलाई की शाम को ही काशी आएंगे। वह सर्किट हाउस में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक, श्री कालभैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे।

कर्मियों को मिलेगा कैशलेस कार्ड

शिक्षकों के कल्याण और स्वास्थ्य सुरक्षा को नई मजबूती देते हुए योगी सरकार काशी से 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' की शुरूआत करने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत वाराणसी के 1,145 बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के 12,407 पात्र शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक तथा अन्य शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 8 जुलाई के प्रस्तावित वाराणसी दौरे के दौरान इस योजना का सुबह 10 बजे टीएफसी में आयोजित कार्यक्रम से इसका शुभारंभ करेंगे। योगी ने शिक्षकों के स्वास्थ्य संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इस योजना की घोषणा की थी। अब इसका शुभारंभ काशी से होने जा रहा है। योजना का उद्देश्य शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को गंभीर बीमारियों के उपचार के दौरान आर्थिक चिंता से मुक्त कर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इससे शिक्षक उपचार की चिंता से मुक्त होकर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। इसे लेकर शिक्षकों में काफी उत्साह है। सहायक अध्यापक तुबा का कहना है कि सरकार की यह योजना शिक्षकों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। सहायक अध्यापक राजीव सिंह ने कहा कैशलेस चिकित्सा योजना शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हजारों शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

विद्यालय एवं लाभार्थियों का विवरण

कुल विद्यालय : 1,145
शिक्षक : 6,580
शिक्षामित्र : 1,538
अनुदेशक : 348
रसोइया : 3,802
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी : 135
स्पेशल एजुकेटर : 4.

क्या E20 Petrol से इंजन खराब हो जाता है? पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर सरकार ने दूर किए ये 10 बड़े भ्रम

अगर आप भी सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स) पर चल रहे उन वीडियो और मैसेज को देखकर परेशान हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा या माइलेज आधा हो जाएगा, तो यह खबर आपके लिए है। अब इन सभी दावों पर केंद्र सरकार ने विस्तार से जवाब दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुक्रवार को 10 अहम बिंदुओं में E20 पेट्रोल से जुड़ी अफवाहों का खंडन किया। सरकार का कहना है कि E20 कार्यक्रम वैज्ञानिक शोध, विशेषज्ञों की रिपोर्ट और कई देशों के अनुभव पर आधारित है।

भूटान ने रिजेक्ट किया भारत का ई20 इथेनॉल फ्यूल

(जीएनएस)।

भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने यानी E20 फ्यूल को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि इसे लेकर देश भर में बड़ा विवाद हो रहा है। अलग-अलग जगहों से वाहन खराब होने या फिर माइलेज के खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसे लेकर काफी विरोध भी रहो रहा है। इसी बीच पड़ोसी देश भूटान ने भारत के इस नए ईंधन को फिलहाल लेने से इनकार कर दिया है।

भूटान ने भारतीय तेल कंपनियों से साफ कहा है कि जब तक भारत में सामान्य पेट्रोल उपलब्ध है, तब तक उसे वही सप्लाई किया जाए। इस फैसले ने E20 पेट्रोल को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

भारत पर पूरी तरह निर्भर है भूटान अपनी पेट्रोल और डीजल की जरूरतों के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर है। इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी भारतीय कंपनियां ही वहां ईंधन की सप्लाई करती हैं। अभी तक भारत भूटान को हाई-क्वालिटी रिफाइंड पेट्रोल भेजता रहा है। लेकिन जब भारतीय कंपनियों ने 20% इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल भेजने का प्रस्ताव दिया, तो भूटान के व्यापार विभाग ने इसे फिलहाल स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे नितिन गडकरी के इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले मिशन को बड़ा झटका लगा है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भूटान के इस फैसले की सबसे बड़ी वजह उसका पुराना ईंधन भंडारण सिस्टम है। देश के पहाड़ी और नमी वाले इलाकों में आज भी ज्यादातर पुराने स्टील के भूमिगत फ्यूल टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन टैंकों में पानी के रिसाव का खतरा रहता है, जो E20 पेट्रोल के लिए बड़ी समस्या बन सकता है।

तकनीकी रूप से इथेनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है, जिसकी वजह से यह हाईग्रोस्कोपिक यानी हवा और आसपास की नमी को तेजी से सोख लेता है। अगर E20 पेट्रोल में थोड़ा भी पानी मिल जाए तो उसे अलग करना मुश्किल हो जाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत भर्ती करने से लेकर हमला करने तक, 23 और पाकिस्तानी कुख्यात अपराधियों को आतंकवादी किया घोषित

(जीएनएस)।

केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति को और सख्त करते हुए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 23 और कुख्यात अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाल के सालों में किसी एक सूची में इतने अधिक व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने की यह सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है।

गृह मंत्रालय का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) से संचालित आतंकी नेटवर्क को कमजोर करना है। सूची में शामिल सभी आरोपी जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और उनके सहयोगी संगठनों से जुड़े बताए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, ये लोग भारत में आतंकी गतिविधियों, घुसपैठ और भर्ती जैसी साजिशों में शामिल रहे हैं।

सरकार का मानना है कि इन 23 लोगों को UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल करने से उनके नेटवर्क, फंडिंग और भर्ती करने वाले सिस्टम पर प्रभावी कार्रवाई करना आसान होगा। साल 2019 में UAPA में हुए संशोधन के बाद सरकार को सीधे किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला था। इससे ऐसे लोगों के वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों पर देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नजर रखना आसान हो जाता है।

नई लिस्ट में मसूद इलियास कश्मीरी का नाम प्रमुख है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, वह आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण और भारत में घुसपैठ कराने में शामिल रहा है। उसे 2022 में जम्मू के सुंजवां सैन्य शिविर पर हुए हमले का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है।

इसके अलावा मोहम्मद मुसद्दीक को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। उस पर सीमा पार से घुसपैठ कराने और सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने का आरोप है। वहीं मुफ्ती मुहम्मद असगर खान पर 2016 के नगरोटा सेना शिविर हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिसमें 7 भारतीय जवान शहीद हुए थे। अब्दुल्लाह जिहादी का नाम भी सूची में शामिल है, जिस पर आतंकी शिविरों के संचालन और घुसपैठ कराने का आरोप है।

लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क पर भी शिकंजा

गृह मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कई बड़े नामों पर भी कार्रवाई की है। इनमें फिरदौस अहमद भट पर जम्मू-कश्मीर में विदेशी आतंकियों की घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई कराने का आरोप है। वहीं हारून रशीद गनई पाकिस्तान से भारतीय युवाओं की भर्ती और हथियारों की व्यवस्था संभालता था। इसके अलावा बिलाल अहमद मीर, आबिद कय्यूम लोन, नजीर अहमद गुज्जर, अब्दुल रऊफ, अशफाक अहमद, हाफिज खालिद वलीद, मौलाना सैफुल्लाह खालिद, मोहम्मद याकूब, मौलाना यूसुफ तैबी, ओवैस फारूक, कारी याकूब शेख, राणा इफ्तिखार, वसीम नूर जाट, मोहम्मद शाहिद फैसल, मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की, हाफिज अब्दुल शकूर, गुलाम फरीद

जैसे कुख्यात नामों को भी आतंकवादी घोषित किया गया है।

'अगले 250 साल लाएं सुख-शांति और समृद्धि', पीएम मोदी ने यूएस स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप को दी बधाई

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों को साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी वैश्विक भलाई की एक ताकत के रूप में रेखांकित किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच की साझेदारी केवल रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, कानून के शासन और दोनों देशों के लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर बनी है।

पीएम मोदी ने लिखा कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लोगों को आपकी स्वतंत्रता की इस ऐतिहासिक 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं।

उन्होंने आगे लिखा कि भारत और अमेरिका केवल एक रणनीतिक साझेदारी ही साझा नहीं करते हैं। लोकतंत्र, कानून के शासन और हमारे लोगों की असीम क्षमता में हमारा साझा विश्वास हमारी दोस्ती को वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों के निरंतर मजबूत होने की उम्मीद जताई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि आने वाले 250 वर्ष अमेरिका के लिए और अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति लेकर आएं और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को देशव्यापी समारोहों, परेडों, आतिशबाजी और विभिन्न ऐतिहासिक कार्यक्रमों के साथ मनाया। यह दिन 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने के 250 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

सांसद अशोक मित्तल ने केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की कर दी मांग

(जीएनएस)।

पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की रहस्यमयी मौत का यह मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग के साथ शुरू हुई यह आवाज अब संसद की दहलीज तक पहुंच चुकी है। मंगेतर सिया गोयल द्वारा खौफनाक साजिश रचकर केतन अग्रवाल की हत्या के मामले के बाद पुरुष भयभीत हैं।

पुरुषों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर ये बेहद संवेदनशील मुद्दा संसद के उच्च सदन राज्यसभा में उठाया गया। राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने देश में 'राष्ट्रीय पुरुष आयोग' के गठन की जोरदार वकालत की। उन्होंने इस मांग के पीछे मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए केतन अग्रवाल की दुखद मौत का प्रमुख रूप से हवाला दिया।

सांसद अशोक मित्तल ने

शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया। इसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, पुणे का केतन अग्रवाल मामला बहुत परेशान करने वाला है। केतन और उनके परिवार को निष्पक्ष, पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच मिलनी चाहिए, और सबसे बढ़कर, उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

मैंने संसद में 'नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल' पेश किया था। हर पीड़ित को न्याय, मदद और कानून के तहत समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। केतन का मामला यह याद दिलाता है कि पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं। उन्हें संस्थागत मदद, कानूनी सुरक्षा और एक ऐसा मंच मिलना चाहिए जहां उनकी बात सुनी जा सके। लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए।

अशोक मित्तल राज्यसभा सांसद हैं। अप्रैल 2022 से आम आदमी पार्टी से सांसद बने थे लेकिन 24 अप्रैल 2026 को डॉ. अशोक मित्तल ने राघव चड्ढ़ा और संदीप पाठक के साथ एक प्रेस कान्फ्रेंस कर आप से इस्तीफा दे दिया था।

8 जुलाई को मीरजापुर आएंगे सीएम योगी, मां विंध्यवासिनी मंदिर में करेंगे दर्शन-पूजन

मीरजापुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ जुलाई को जनपद में आएंगे। वे हेलीकॉप्टर द्वारा 11 बजकर 10 मिनट पर वाराणसी के पुलिस लाइन से चलकर साढ़े 11 बजे विंध्याचल के हैलीपैड पर उतरेंगे। वहां से 11.35 वहां कार से मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान 11: 55 तक मां का दर्शन पूजन करेंगे। 12:05 पर अष्टभुजा अतिथि गृह के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां विंध्याचल मंडल के लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यो की समीक्षा करने के साथ ही नए कार्यो के कार्य योजनाओं के संबंध में जानकारी लेंगे। दोपहर एक बजे से डेढ़ बजे तक अष्टभुजा अतिथि ग्रह में विश्राम करेंगे। एक बजकर 40 मिनट पर चित्रकूट जिले के लिए हेलीकाप्टर से रवाना हो जाएंगे।

चंपत राय के समर्थन में उतरे अयोध्या के साधु-संत, राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे को लेकर की ये अपील

राम मंदिर दान चोरी मामले में इस्तीफा देने वाले ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में साधु-संत उतर आए हैं। उन्होंने ट्रस्ट से इस्तीफा न स्वीकार करने की अपील की है।

(जीएनएस)।

अयोध्याः अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को संत समाज उनके समर्थन में उतर आया। संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से अपील की कि वह चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न करे। अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संतों ने चंपत राय की ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उनका मकसद उनकी सार्वजनिक छवि को खराब करना है।

पारदर्शी व्यवहार की बात

अयोध्या के संतों ने कहा कि चंपत राय दशकों से राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण से गहराई से जुड़े रहे हैं। उनका सार्वजनिक जीवन पारदर्शिता और समर्पण से भरा रहा है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है और यह उन्हें बदनाम करने की एक अनावश्यक कोशिश है।

संतों ने कहा कि इस विवाद के दौरान चंपत राय का व्यवहार पूरी तरह पारदर्शी रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाने की मांग की थी, जिससे यह साबित होता है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उन्हें पूरी जांच से कोई आपत्ति नहीं है।

एसआईटी बनाने का स्वागत

एसआईटी बनाने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए संतों ने कहा कि जांच से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि विवाद के बावजूद चंपत राय ने संयम बरता और सार्वजनिक बयान देने से बचे। उनके प्रति एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या के संत मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। उन्हें अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद दे रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संतों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के सामने कई सवाल भी उठाए। उन्होंने मंदिर के फंड की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों पर सवाल उठाए और जानना चाहा कि पर्याप्त सावधानी क्यों नहीं बरती गई।

बैठक पहले बुलाने पर सवाल

संतों ने यह भी पूछा कि ट्रस्ट की प्रस्तावित बैठक समय से पहले क्यों बुलाई गई और इस फैसले की क्या

जरूरत थी। संतों ने मांग की कि ट्रस्ट इन मुद्दों पर स्पष्ट जवाब दे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है और भ्रम और विवाद से बचने के लिए मंदिर से जुड़े सभी मामलों में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। बाद में कई संतों ने चंपत राय के लिए अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

संत राघवेश दास वेदांती ने कहा कि अयोध्या के संत ट्रस्ट से मांग कर रहे हैं कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। एसआईटी ने जिन आरोपियों को पकड़ा है, उन्हें रिमांड पर लिया गया है। कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी और सब कुछ साफ हो जाएगा।

चंपत पर आरोप बेबुनियाद

राम कचहरी मंदिर के महंत शशिकांत दास ने बताया कि चंपत को दोषी ठहराया जा रहा है, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसमें चंपत की कोई गलती नहीं है। उन्हें हटाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है ताकि असली दोषी राम मंदिर को लूट सकें। वैदेही भवन के महंत वैदेही वल्लभ शरण ने भी चंपत राय का समर्थन करते हुए कहा कि संघ का हर प्रचारक ईमानदार होता है। संघ के प्रचारक समर्पित और अडिग होते हैं। ये कुछ बादल हैं, जो जल्द ही छंट जाएंगे।

इस बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 6 जुलाई को एक अहम बैठक करने वाला है, जिसमें सदस्य ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। बैठक में मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने और राम मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़ी कथित गड़बड़ियों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की जांच पर भी चर्चा की जाएगी।

डिजिटल लाइब्रेरी में लगी आग, मची भगदड़; लखनऊ जैसा हादसा अलीगढ़ में होने से बचा...धुआं भरने से घुटने लगा दम

अलीगढ़ के सरसौल चौराहा स्थित एस्पिरेन्ट डिजिटल लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया क्योंकि घटना के समय कोई मौजूद नहीं था।

(जीएनएस)।

अलीगढ़। लखनऊ में हाल ही में हुए कोचिंग अग्निकांड के बाद भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। प्रशासनिक कार्रवाई के बाद भी जिले में बिना मान्यता के कोचिंग सेंटर संचालित हैं, जो सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं। शुक्रवार सुबह सरसौल चौराहा पर नीवरी हाउस की दूसरी मंजिल पर संचालित ऐसी ही एस्पिरेन्ट डिजिटल लाइब्रेरी में अचानक आग लग गई। इससे अफरा-तफरी मच गई।

समय रहते दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। अग्निशमन विभाग को सुबह करीब 7:36 बजे डायल-101 पर नीवरी हाउस की दूसरी मंजिल से धुआं निकलने की सूचना मिली थी। कुछ ही देर में अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में दो दमकल वाहन घटनास्थल पर पहुंचे।

मौके पर पहुंचने पर पता चला कि लाइब्रेरी के अंदर लगे सीलिंग फैन में शार्ट सर्किट होने से आग लग गई थी, जिसके कारण पूरी लाइब्रेरी धुएं से भर गई। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। दूसरी टीम ने स्मोक एग्जास्टर लगाकर इमारत से धुआं बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

राहत की बात यह रही कि घटना के समय लाइब्रेरी में कोई मौजूद नहीं था, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग में कुछ पंखे और लाइब्रेरी का सामान क्षतिग्रस्त हुआ है। सीओ बन्नादेवी धनंजय सिंह ने बताया कि हादसे के समय लाइब्रेरी में कोई नहीं था। पंजीकरण भी नहीं मिला है। संबंधित विभागों से भी जानकारी कराई जा रही है।

क्या दिखावे की हो रही कार्रवाई

लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद अलीगढ़ प्रशासन और विकास प्राधिकरण शहरभर में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच अभियान चला रहे हैं। शिक्षा विभाग ने भी बिना मान्यता चल रहे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की, इसके बाद भी शहर में बिना मान्यता के ऐसे संस्थान हैं।

डिजिटल लाइब्रेरी में लगी यह आग सुरक्षा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। सवाल उठ रहे हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई क्या केवल दिखावे तक सीमित रही गई है।

15 संस्थान किए जा चुके हैं सील

लखनऊ में हुई आग की घटना के बाद शहरभर में चलाए गए निरीक्षण अभियान के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर अब तक कुल 15 कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरियों को सील किया जा चुका है।

इनमें ग्रेविटी कोचिंग सेंटर, कटारा कोचिंग सेंटर, अलीगढ़ काम्पीटिशन क्लासेज, शर्मा जी क्लासेज, डिजिटल लाइब्रेरी, अनन्या क्लासेज, प्रारंभ आईएएस स्टडी सर्किल, सीए नैया सचदेव क्लासेज, लावनिया लाइब्रेरी, स्टडी फोकस क्लासेज, प्रमोद कुमार लाइब्रेरी, सक्सेस लाइब्रेरी, इंस्पायरी लाइब्रेरी (मेडिकल रोड), किंजा लाइब्रेरी और बंसल क्लासेज शामिल हैं।

प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट पाया गया है। जिस समय यह हादसा हुआ, उस समय लाइब्रेरी बंद थी, जिसके कारण एक बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। आग से कुछ पंखे और लाइब्रेरी का अन्य सामान जल गया। - मुकेश कुमार, मुख्य अग्निशमन अधिकारी

अयोध्या में राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने महिला को दी नई जिंदगी, ऑपरेशन कर पेट से निकाला 10 किलो का ट्यूमर

(जीएनएस)।

अयोध्या। राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शननगर के चिकित्सकों ने महिला के पेट से दस किलो का ट्यूमर ऑपरेशन करके निकाला है। महिला गोंडा जिले की मनकापुर निवासी है। वह पांच वर्षों से उपचार गोंडा में ही करा रही थी। महिला को शुरूआती दौर में 500 ग्राम का ट्यूमर होने की जानकारी मिल थी।

उपचार आरंभ होने के बाद पांच वर्षों में बढ़कर दस किलो पहुंच गया। हालत बिगड़ने पर आठ जून को मेडिकल कॉलेज में पहुंची थी। ओपीडी में जर्नल सर्जन डॉ. प्रदीप सिंह ने भर्ती कर जांच कराई और शुक्रवार को विभागाध्यक्ष डॉ. एमसी पांडेय की निगरानी में डॉ. प्रदीप ने ऑपरेशन किया। महिला पूरी तरह स्वस्थ है।

मनकापुर बाजार निवासी प्रमोद

कुमार मोदनवाल की 40 वर्षीय पत्नी यशोदा तीन वर्ष पहले पेट दर्द होने के बाद चिकित्सक के पास पहुंचीं। अल्ट्रासाउंड कराने पर ट्यूमर निकला। इसके बाद स्वजन बस्ती के एक अस्पताल में ले जाकर चिकित्सक को दिखाया। चिकित्सक ने उपचार के साथ आपरेशन की सलाह दी, लेकिन ऑपरेशन से मना किया।

एक वर्ष उपचार के बाद मनकापुर के ही होम्योपेथिक चिकित्सक से दवा शुरू कर दिया। इसके बाद ट्यूमर काफी बढ़ गया, तो रामनगरी के एक निजी चिकित्सक के पास पहुंचे। वहां डॉक्टर ने रिपोर्ट देख सीधे डॉ. प्रदीप सिंह के पास मेडिकल कॉलेज भेज दिया।

डॉ. श्रृष्टेश ने बताया कि भर्ती करने के बाद सबसे पहले जांच में कैंसर की आशंका दूर करने के लिए सैंपल भेज अस्पताल से संबंधित दूसरी जांच और ब्लड की कमी को दूर करने के लिए उपचार चलता रहा। शुक्रवार को सभी रिपोर्ट नार्मल होने पर डॉ. प्रदीप सिंह ने डॉ. दिव्या उपाध्याय, डॉ. श्रृष्टेश तिवारी, डॉ. पीयूष कांत और बेहोशी की डॉ. नेहा सिंह तथा डॉ. अमन के साथ मिलकर ऑपरेशन कर दिया। ट्यूमर के साथ करीब तीन से चार लीटर पानी भी निकला।

मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों के डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। जनरल सर्जनों का बहुत ही सराहनीय प्रयास चल रहा है। उनके इसी प्रयास से जनता को काफी राहत मिल रही है।

- डॉ. दिनेश सिंह मार्तोलिया, प्राचार्य

प्रतापगढ़ में सीएम योगी का दौराःसुरक्षा चाक-चौबंद, व्यापक तैयारियां आरम्भ, आईजी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश

इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े सुधार कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दे रहे हैं. उनका उद्देश्य भूमि विवादों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना और राजस्व न्याय प्रणाली को आधुनिक व तकनीक आधारित बनाना है.

इसी के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है. इसका मकसद इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता लाना है. इस व्यवस्था के तहत लखनऊ और प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणियों के सभी लंबित और नए मुकदमों को अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष ही पेश किया जाएगा.

हर बुधवार को होगी मामलों की सुनवाई

अर्चना अग्रवाल ने ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज न्यायालय के लिए अलग-अलग तीन सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है, जो हर बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की करेंगी. इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता आएगी. वहीं, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस श्रेणी के सभी लंबित एवं नए प्रकरणों की पहचान कर उन्हें निर्धारित विशेष पीठ के पास दर्ज कराएं.

राजस्व व्यवस्था अधिक उत्तरदायी

गौरतलब है कि योगी सरकार पहले ही राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों की दिशा में कई सराहनीय पहल कर चुकी है. डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन नामांतरण एवं अन्य राजस्व सेवाएं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भूमि पैमाइश, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे कदमों ने राजस्व व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाया है.

अयोध्या में 5.61 लाख के केसीसी बकाया पर किसान के खेत की कुर्की, प्रशासन ने लगाई लाल झंडी

अयोध्या में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के 5.61 लाख रुपये के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण का भुगतान न करने पर तहसील प्रशासन ने एक किसान के खेत की कुर्की कर दी .

(जीएनएस)।

शुजागंज (अयोध्या)। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा मवई से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत लिया गया 5.61 लाख रुपये का ऋण न चुकाने पर तहसील प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायेदार किसान के खेत की कुर्की कर दी। राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में खेत पर लाल झंडी लगाकर कुर्की आदेश का पालन कराया गया।

मवई थाना क्षेत्र के ग्राम ओहरामऊ सहजना निवासी राज कुमार पुत्र काशीराम पर बैंक के अनुसार 5,61,544 रुपये का बकाया था। बैंक द्वारा कई बार नोटिस जारी कर भुगतान का अवसर दिए जाने के बावजूद राशि जमा न होने पर राजस्व वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई। सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद तहसील प्रशासन ने खेत की कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई।

कार्रवाई के दौरान तहसीलदार विजय कुमार, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा मवई के शाखा प्रबंधक रोहित श्रीवास्तव तथा मवई पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अधिकारियों ने खेत पर लाल झंडी लगाकर कुर्की की औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराई।

शाखा प्रबंधक रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि बकाया राशि का भुगतान होने तक नियमानुसार आगे की राजस्व वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने किसानों से समय पर ऋण अदायगी करने की

अपील करते हुए कहा कि इससे ऐसी कठोर कार्रवाई से बचा जा सकता है।

योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब तीन सदस्यीय स्पेशल बेंच करेगी सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई, जानिए क्या है नई व्यवस्था

इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए लगातार बड़े सुधार कर रही है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद ने सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों के निस्तारण को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब आरक्षित श्रेणी की भूमि, शासकीय भूमि, ग्राम सभा, नजूल, निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है.

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सरकारी और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने पर जोर दे रहे हैं. उनका उद्देश्य भूमि विवादों का समय पर निस्तारण सुनिश्चित करना और राजस्व न्याय प्रणाली को आधुनिक व तकनीक आधारित बनाना है.

इसी के तहत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-9 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नई व्यवस्था लागू की गई है. इसका मकसद इन संवेदनशील मामलों के निस्तारण में पारदर्शिता, न्यायिक गुणवत्ता और एकरूपता लाना है. इस व्यवस्था के तहत लखनऊ और प्रयागराज स्थित राजस्व परिषद न्यायालयों में इन श्रेणियों के सभी लंबित और नए मुकदमों को अब तीन सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष ही पेश किया जाएगा.

हर बुधवार को होगी मामलों की सुनवाई

अर्चना अग्रवाल ने ने बताया कि राजस्व परिषद ने लखनऊ और प्रयागराज न्यायालय के लिए अलग-अलग तीन सदस्यीय विशेष पीठों का गठन किया है, जो हर बुधवार को नियमित रूप से इन मामलों की सुनवाई की करेंगी. इस पहल से सरकारी और सार्वजनिक भूमि से जुड़े संवेदनशील मामलों का समय पर निस्तारण संभव होगा, साथ ही पूरे प्रदेश में निर्णय प्रक्रिया में एकरूपता आएगी. वहीं, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस श्रेणी के सभी लंबित एवं नए प्रकरणों की पहचान कर उन्हें निर्धारित विशेष पीठ के पास दर्ज कराएं.

राजस्व व्यवस्था अधिक उत्तरदायी

गौरतलब है कि योगी सरकार पहले ही राजस्व प्रशासन में व्यापक सुधारों की दिशा में कई सराहनीय पहल कर चुकी है. डिजिटल भू-अभिलेख, ऑनलाइन नामांतरण एवं अन्य राजस्व सेवाएं, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भूमि पैमाइश, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी भूमि की सुरक्षा जैसे कदमों ने राजस्व व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाया है.

आर्थिक तंगी नहीं बनेगी बाधा! 865 होनहारों को सरकार देगी फ्री हॉस्टल, किताबें और टॉप क्लास कोचिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में यूपी सरकार ने SC, ST और OBC के गरीब व होनहार युवाओं के लिए 'निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना' शुरू की है

निःशुल्क आईएएस-पीसीएस कोचिंग योजना से बदलेगा यूपी के होनहारों का भविष्य

यूपी सरकार की निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना।

865 छात्रों को मुफ्त रहना, खाना और उच्च स्तरीय कोचिंग।

प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई 2026 को, कक्षाएं 1 अगस्त से।

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के गरीब व होनहार युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं में भेजने के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'निःशुल्क आईएएस-पीसीएस आवासीय कोचिंग योजना' आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अब राज्य के प्रतिभावान छात्रों को देश और प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं (वढरउ और वढढरउ) की तैयारी पूरी तरह निशुल्क कराई जाएगी।

5 जुलाई को 10 हजार से अधिक अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य

इस योजना के अंतर्गत दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 5 जुलाई 2026 को प्रदेश के सभी मंडलों में

प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 10,175 छात्र-छात्राएं शामिल होने जा रहे हैं। परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद पारदर्शी काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों की छंटनी होगी। चयनित छात्र-छात्राओं के लिए नियमित कक्षाएं 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ हो जाएंगी और यह विशेष शैक्षणिक सत्र 31 मई 2027 तक संचालित किया जाएगा।

प्रदेश भर में स्थापित सात अत्याधुनिक आवासीय कोचिंग सेंटरों में कुल 865 चयनित अभ्यर्थियों को मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। सरकार ने इसमें एक विशेष व्यवस्था भी की है, जिसके तहत 25 प्रतिशत सीटें उन छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं जो लेटरल एंट्री के माध्यम से प्री परीक्षा पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं। चयनित युवाओं को हॉस्टल में रहने, पौष्टिक भोजन, बेहतरीन पुस्तकें, स्टडी मटेरियल और देश के अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन जैसी सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्यमंत्री का विजनः आर्थिक तंगी से नहीं होगा समझौतो का दौर

यह योजना महज एक कोचिंग कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा विजन है। मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि आर्थिक तंगी या संसाधनों का अभाव किसी भी प्रतिभाशाली छात्र के भविष्य और उसके बड़े सपनों के आड़े नहीं आना चाहिए। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार इन होनहारों की पढ़ाई का पूरा खर्च खुद उठा रही है।

निजी कोचिंग के लाखों के खर्च से मिलेगी मुक्ति

वर्तमान दौर में जहां निजी संस्थानों में आईएएस-पीसीएस की तैयारी के नाम पर लाखों रुपये की फीस वसूली जाती है, वहीं गरीब परिवारों के बच्चों के लिए यह खर्च उठा पाना नामुमकिन होता है। समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह के अनुसार, योगी सरकार की इस पहल से वंचित और शोषित वर्ग के युवाओं में नया आत्मविश्वास जगा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही दिशा मिलने से अब ये युवा भी ब्यूरोक्रेसी (प्रशासनिक सेवाओं) में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराएंगे, जिससे आने वाले समय में समाज में एक बेहद सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

ईंरान को जल्द मिलेंगे उसके फंसे हुए अरबों डालर

ईंरान–अमेरिका के युद्ध में कितनी तबाही हुई है, बताने की जरूरत नहीं है लेकिन संभव है कि ईंरान को वास्तव में इस युद्ध से लाभ हो सकता है। यह मैं इसलिए कहा रहा हूं कि ईंरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया। दावा किया गया कि कतर में पंसी ईंरान की 12 अरब डॉलर की राशि में से 6 अरब डॉलर जल्द जारी कर दिए जाएंगे।

कुम शहर में एक कार्यव्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा ईंरान–अमेरिका डील के तहत असेट रिलीज करने की पहली किश्त होगी जो उसे कतर से मिलेगी। उन्होंने यह महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता और इस्लामाबाद में हुए समझौते के तहत यह राशि रिलीज हो रही है। बाकी 6 अरब डॉलर की वापसी के लिए भी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। पेजेशकियन ने बताया कि शांति समझौते के तहत ईंरान के तेल और पेट्रोवैमिकल क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए है।

उन्होंने इसे ईंरानी जनता की बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि इन प्रतिबंधों के हटने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलेगी। ईंरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने राष्ट्रपति के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राष्ट्रपति ने हाल के संघर्ष का जिव्र करते हुए ईंरानी जनता की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर, मंत्री, सेना कमांडर, बुद्धिजीवी और आम नागरिक भी संकट के समय एकजुट रहे। राष्ट्रपति ने बताया कि संघर्ष के बाद सरकार पुर्ननिमाण कार्य शुरू कर चुकी है। आम लोगों को रहात देने के लिए खाद्दा सब्सिडी बढ़ाने और अतिरित्त वित्तीय सहायता देने की योजनाएं भी लागू की जा रही हैं। ईंरान के इस दावे से उम्मीद है कि देश की अर्थव्यवस्था को वुछ राहत मिलेगी। कतर में पंसा पैसा रिलीज होने से तेल निर्यात और अन्य क्षेत्रों में सुधार आ सकता है।

यह घटनाम ईंरान की विदेश नीति और आर्थिक रणनीतिक में नई दिशा दिखाता है, हालांकि अब तक ईंरान में होने वाले 300 बिलियन डॉलर के निवेश को लेकर कोई बात साफ नहीं हुई है। ये पंड कहां से आएगा, कब आएगा इस पर वुछ नहीं कहा गया।

विदेशों में ईंरान की वुल जब्त या प्रतिबंधित संपत्ति का अनुमान लगभग 100 अरब डॉलर है। इस प्रतिबंधित खातों में तेल से होने वाली कमाई, विदेशी मुद्रा भंडार, बैंकिग संपत्ति व अन्य दावे शामिल हैं। पहली बार बड़े पैमाने पर संपत्ति तब प्रीज की गई, जब ईंरान में इस्लामिक व्रांति हुई और अमरीरिकी दूतावास में बंधक संकट पैदा हुआ। 14 नवम्बर 1979 को ईंरानी व्रांतिकारियों द्वारा तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में मौजूद ईंरानी सरकार की संपत्ति को ब्लॉक कर दिया। 1980 में ईंरान सरकार की लगभग 12 अरब डॉलर की संपत्ति जब्त की गई थी जो ज्यादातर अमेरिकी बैंकों में थी। इसमें नकद, सोना, कई अन्य होल्डिंग्स शामिल थी। इसमें से अधिकांश संपत्ति 1981 के अल्जीयर्स समझौते के तहत जारी कर दी गई थी, जिससे बंधक संकट समाप्त हुआ था। लगभग 4 महीने के युद्ध के बाद अमेरिका–ईंरान शांति समझौते की रूपरेखा पर सहमत हुए हैं। इसके बावजूद ईंरान की जब्त संपत्तियों पर अड़चन बनी हुई है। एक तरफ ईंरान ने 14 सूत्री समझौते के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिका बातचीत शुरू होने से पहले जब्त संपत्ति जारी करने पर सहमत हो। पर ट्रंप के कई बार विरोधाभासी बयानों ने स्थिति को असमंजस में डाल रखा है।

यूपी चुनाव 2027 के लिए चक्रव्यूह की रचना के लिये मिले दो दिग्गज

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले लखनऊ का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है. अयोध्या में चढ़ावा कांड के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंच गए हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ सहित राज्य के दोनों डिप्टी सीएम ने एयरपोर्ट पर नितिन नवीन का स्वागत किया. इस दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले नितिन नवीन के गले में भगवा पटका पहनाया. इसके बाद दोनों ने मंद–मंद मुस्कुराया. दोनों की इस मुस्कुराहट बता रहा है कि यूपी चुनाव 2027 के लिए चक्रव्यूह की रचना दिल्ली से लखनऊ पहुंच गया है.

(जीएनएस)।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी भले ही दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी गोटियां सेट करना शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में शनिवार को देश की सियासत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेहद खास और अहम हलचल देखने को मिली. दिल्ली की सियासी गलियारों से निकलकर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय सांगठनिक दौरे पर सीधे नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे हैं.

हवाई अड्डे पर जब नितिन नवीन उतरे, तो उनके सीएम योगी ने सबसे पहले उनके गले में चमचमाता हुआ भगवा पटका पहनाया. दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास से भरी गहरी मुस्कान थी. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एयरपोर्ट पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेहद भव्य और जोशीला स्वागत किया. इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे.

योगी–नवीन की मुलाकात के राजनीतिक मायने

इस खास मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह साफ मैसेज चला गया है कि बीजेपी आलाकमान और सीएम योगी की यह जोड़ी आगामी यूपी चुनाव 2027 के लिए

एक अभेद्य किला तैयार करने में जुट गई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश में यह दूसरा दौरा है, इससे पहले वह पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में मथुरा में सीएम योगी के साथ मंच शेयर कर चुके हैं. लेकिन अब यूपी चुनाव 2027 के लिए प्रदेश की नई सांगठनिक टीम के गठन के तुरंत बाद यह दौरा हो रहा है. उनके इस मुस्कुराते हुए चेहरे और भगवा पट्टे के पीछे एक बेहद मजबूत और कड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है.

योगी और नवीन की जोड़ी की क्या है तैयारी?

पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार के बीच चल रही कथित अनबन की अटकलों को इस दौरे ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद अगवानी के लिए खड़े होना यह दिखाता है कि केंद्रीय नेतृत्व और राज्य सरकार पूरी तरह एक है. गले में भगवा पट्टा इस बात का साफ प्रतीक है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी मूल विचारधारा हिंदुत्व के कोर एजेंडे से रत्ती भर भी पीछे हटने वाली नहीं है, बल्कि इसे सीएम योगी के 'लॉ एंड ऑर्डर' और विकास मॉडल के साथ जोड़कर 2027 के रण में उतरा जाएगा. अयोध्या कांड के बाद नवीन का यह पहला दौरा है.

दो दिनों के महा–मंथन में क्या प्लानिंग करेगी 'योगी–नवीन' की जोड़ी?

नितिन नवीन लखनऊ में रहकर मैराथन बैठकें कर रहे हैं. सूत्रों की मानें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, दोनों उपमुख्यमंत्री और आरएसएस के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ मिलकर आगामी तीन दिनों के रोडमैप पर मुख्य रूप से इन 3 बड़े बिंदुओं पर चक्रव्यूह रचा जा रहा है:

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ के राज्य मुख्यालय में नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के साथ–साथ 'शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन' को भी संबोधित करेंगे. बीजेपी का पुराना नारा रहा है, 'बूथ जीता तो चुनाव जीता'. लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों से सबक लेते हुए, बीजेपी इस बार अति–आत्मविश्वास से बचकर हर छोटे मोर्चे पर बारीकी से काम कर रही है.

पार्टी सूत्रों का कहना है 'नितिन नवीन का यह दो दिवसीय दौरा यूपी के कार्यकताओं में वह 'इलेक्ट्रिक एनर्जी' भरने आया है जिसकी जरूरत आगामी चुनावी जंग के लिए है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरी रणनीति की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. मंत्रियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे जिलों में कैंप करें और सीधे जनता से फीडबैक लें.'

ईशा मालवीय ने पीएम मोदी के हमशक्ल को समझ लिया असली प्रधानमंत्री, झुककर किया नमस्ते तो छूटी सबकी हंसी

ईशा मालवीय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के हमशक्ल को असली मोदी जी समझ लिया और उन्हें झुककर नमस्ते भी कहने लगीं। ईशा के रिएक्शन को लेकर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम ईशा मालवीय का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है। मुंबई में एक पब्लिक इवेंट के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को कुछ पल के लिए असली प्रधानमंत्री समझ लिया। यह घटना एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान हुई, जहां ईशा रेड कार्पेट पर मीडिया और मेहमानों से बातचीत कर रही थीं। ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में एक्ट्रेस को हैरानी से रिएक्शन देते हुए देखा जा सकता है, जब उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा दिखता था।

जैसे ही उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी, ईशा मालवीय चौंक गईं और मुस्कुराते हुए बोलीं, 'ओह, मोदी जी!' उनके इस रिएक्शन पर वहां मौजूद लोगों की हंसी छूट पड़ी। कुछ ही पल बाद, एक्ट्रेस को एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि उनका हमशक्ल है। उन्होंने इस स्थिति को मजाकिया अंदाज में लिया, उस व्यक्ति से हाथ मिलाया और फोटो के लिए पोज दिया। कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने मजाक में कहा, 'दोस्तों, हमारे

साथ मोदी जी हैं।'

ईशा मालवीय की क्लिप

यह क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इस घटना पर मजेदार रिएक्शन्स दिए। कई लोगों ने मुस्कुराते हुए स्थिति को संभालने के लिए ईशा की तारीफ की, जबकि कुछ लोगों ने उस जबरदस्त समानता पर कमेंट किया जिसकी वजह से यह कन्फ्यूजन हुआ।

कौन हैं विकास महंते?

वीडियो में दिखने वाले व्यक्ति विकास महंते हैं, जो मुंबई के एक बिजनेसमैन, एक्टर और सोशल वर्कर हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी शक्ल–सूरत के लिए काफी मशहूर हैं। पिछले कुछ सालों में, महंते ने अपने लुक, दाढ़ी के स्टाइल और तौर–तरीकों की वजह से पब्लिक इवेंट्स में लोगों का ध्यान खींचा है। कई लोगों को उनकी हरकतें प्रधानमंत्री जैसी ही लगती हैं।

विकास महंते की फिल्में

महंते ने अलग–अलग राज्यों में कई पॉलिटिकल कैंपेन इवेंट्स और पब्लिक प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया है। बताया जाता है कि उन्हें चुनाव प्रचार और जागरूकता अभियानों के दौरान देखा गया है, जहां मोदी जैसी उनकी शक्ल–सूरत अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। पब्लिक में दिखने के अलावा, महंते ने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी हाथ आजमाया है। वह फिल्मों और स्क्रीन प्रोडक्शंस में नजर आ चुके हैं, जिसमें 'हैप्पी न्यू ईयर' में एक छोटा सा रोल (कैमियो) भी शामिल है। इसके अलावा, वह 'मोदी काका का गांव', 'द साबरमती रिपोर्ट', और 'एक नया सवेरा' जैसे प्रोजेक्ट्स से भी जुड़े रहे हैं।

ईशा मालवीय कौन हैं?

वहीं, ईशा मालवीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक पॉपुलर चेहरा बनी हुई हैं। उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और 'मिस मध्य प्रदेश' समेत कई ब्यूटी पेजेंट के खिताब जीते। उनके एक्टिंग करियर को टीवी शो 'उड़ारियां' से रफ्तार मिली, जिसमें जैस्मीन कौर संधू के किरदार में उन्हें काफी पहचान मिली। भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले रियलिटी शो में से एक 'बिग बॉस 17' में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई।

इंटरनेट पर वायरल है वीडियो

हालांकि यह वायरल वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड का था, लेकिन ईशा के तुरंत रिएक्शन और उस आदमी की प्रधानमंत्री से हैरान कर देने वाली मिलती–जुलती शक्ल (जिसे उन्होंने शुरू में प्रधानमंत्री समझा था) की वजह से यह ऑनलाइन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले एंटरटेनमेंट क्लिप्स में से एक बन गया है।

वैभव सूर्यवंशी नहीं सबसे युवा डेब्यूटेंट, कौन है वह पाकिस्तानी जिसने 14 साल में खेला पहला इंटरनेशनल गेम?

(जीएनएस)।

भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में जब 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा, तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। बिहार के समस्तीपुर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने वाले इस युवा बल्लेबाज ने डेब्यू के साथ ही सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया और भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उनकी इस उपलब्धि से पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई।

हालांकि वैभव सूर्यवंशी की यह उपलब्धि जितनी बड़ी है, उतनी ही दिलचस्प एक और सच्चाई भी है। भारत का रिकॉर्ड अपने नाम करने के बावजूद वह विश्व क्रिकेट के सबसे युवा इंटरनेशनल डेब्यूटेंट नहीं बन

सके। यह रिकॉर्ड आज भी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर के नाम दर्ज है, जिसने महज 14 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखकर इतिहास रचा था।

कौन है यह पाकिस्तानी खिलाड़ी?

विश्व क्रिकेट में सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम दर्ज है। उन्होंने साल 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल और 227 दिन थी। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट में भी पदार्पण कर सबसे कम उम्र में दोनों प्रारूपों में खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया।

वैभव सूर्यवंशी ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया। इस तरह वह दुनिया के सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए, लेकिन हसन रजा का रिकॉर्ड अब भी बरकरार है।

डेब्यू मैच में सूर्यवंशी ने दिखाया आक्रामक रुख

पहले ही मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ज्यादा नहीं चल पाया लेकिन धमाल मचाने में वह पीछे नहीं रहे। उन्होंने तूफानी अंदाज में खेलते हुए तहलका मचा दिया और आर्चर का पहली बार सामना करते हुए छक्का जमा दिया। 10 गेंदों में 14 रन की छोटी पारी में उनके दो छक्के थे। टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में छक्का जड़ने के मामले में सूर्यवंशी टॉप पर आ गए।

क्या बैन हो गई सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' ? सेंसर ने लगा दी रोक? मेकर्स ने सामने रखा ऐसा सच

(जीएनएस)।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि' इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हालांकि इस बार वजह फिल्म की कहानी या स्टारकास्ट नहीं बल्कि उससे जुड़ी वो खबरें हैं जिनमें दावा किया जा रहा था कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिलने में परेशानी आ रही है।

'मातृभूमि' को लेकर फैली अफवाहों पर आया आधिकारिक बयान

इन चचाओं ने सोशल मीडिया पर तेजी से जोर पकड़ा, जिसके बाद

दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। लेकिन अब इन अफवाहों पर निमार्ताओं ने खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

सलमान खान फिल्म्स ने जारी किया स्पष्टीकरण

फिल्म के प्रोडक्शन हाउस Salman Khan Films ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन सभी रिपोर्ट्स को पूरी तरह गलत बताया गया है, जिनमें कहा जा रहा था कि फिल्म का सर्टिफिकेशन रोक दिया गया है या उसे किसी तरह की सेंसर संबंधी बाधा का सामना करना पड़ रहा है। निमार्ताओं ने स्पष्ट किया कि फिल्म को लेकर फैल रही ऐसी खबरों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और दर्शकों को अपुष्ट जानकारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए।

अभी सेंसर बोर्ड के पास पहुंची ही नहीं फिल्म

निमार्ताओं द्वारा शेयर किए गए बयान में ये भी बताया गया कि 'मातृभूमि' को अभी तक प्रमाणन प्रक्रिया के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजा ही नहीं गया है। ऐसे में फिल्म के सर्टिफिकेशन को रोके जाने या किसी तरह की आपत्ति लगाए जाने की बातें पूरी तरह निराधार हैं। इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में चल रही अटकलें महज अफवाह थीं और फिल्म फिलहाल अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है।

फैंस से की गई खास अपील

सलमान खान फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस ने दर्शकों और मीडिया से ये भी अनुरोध किया है कि फिल्म से जुड़ी किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। निमार्ताओं का कहना है कि मातृभूमि से संबंधित सभी आधिकारिक अपडेट केवल उनके अधिकृत प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। इस अपील का मकसद फिल्म को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाना और दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाना है।

देशभक्ति के रंग में नजर आएंगे सलमान खान

'मातृभूमि' को एक देशभक्ति से प्रेरित फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म में सलमान खान एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। लंबे समय बाद उन्हें ऐसे किरदार में देखने के लिए उनके फैंस के बीच खास उत्साह बना हुआ है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। दोनों की जोड़ी को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है।

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?

–फिल्म 'मातृभूमि' के रिलीज शेड्यूल की बात करें तो ये इसी साल अगस्त में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है। फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं, जो इससे पहले कई चर्चित फिल्मों और प्रोजेक्ट्स का निर्देशन कर चुके हैं। निमार्ताओं को उम्मीद है कि देशभक्ति, एक्शन और भावनात्मक तत्वों से भरपूर ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल रहेगी।

–फिलहाल सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर सेंसर बोर्ड से जुड़े विवादों की खबरों पर पूरी तरह विराम लग गया है। निमार्ताओं ने साफ कर दिया है कि फिल्म को अभी तक सर्टिफिकेशन के लिए भेजा ही नहीं गया है, इसलिए बैन या सर्टिफिकेशन रोकने जैसी बातें पूरी तरह गलत हैं। अब फैंस की नजर फिल्म की रिलीज और उससे जुड़े अगले बड़े अपडेट पर टिकी हुई है।

57 साल की हिंदू एक्ट्रेस की शादीशुदा मुस्लिम म्यूजिक कंपोजर ने बर्बाद की जिंदगी, दर्दनाक बना करियर

(जीएनएस)।

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाए बिना भी दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। प्रतिभा सिन्हा भी उन्हीं नामों में शामिल हैं। फिल्मों में लंबी पारी भले ही न खेल पाईं लेकिन एक गाने ने उन्हें ऐसी पॉपुलैरिटी दिलाई कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं।

एक सुपरहिट गाने ने बदल दी थी पहचान

4 जुलाई 1969 को कोलकाता में जन्मीं प्रतिभा सिन्हा मशहूर एक्ट्रेस माला सिन्हा (टं' ग्रल्लँ) की बेटी हैं। आज प्रतिभा सिन्हा का 57वां जन्मदिन है। फिल्मी माहौल में पली–बढ़ीं प्रतिभा सिन्हा ने भी अपनी मां की तरह फिल्मी दुनिया में कदम रखा और इस जगत में सफलता हासिल करने का सपना देखा। हालांकि उनकी मंजिल वैसी नहीं रही जैसी उन्होंने कल्पना की थी।

बॉलीवुड में रखा कदम लेकिन किस्मत ने नहीं दिया साथ

–प्रतिभा सिन्हा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म 'महबूब मेरे महबूब' से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया लेकिन वह पहचान हासिल नहीं कर सकीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी।

–प्रतिभा सिन्हा के करियर का सबसे यादगार मोड़ साल 1996 में आया, जब फिल्म राजा हिंदुस्तानी (फ्रं ळल्ल४२३ल्ल) का गाना 'परदेसी–परदेसी' रिलीज हुआ था। इस गाने में प्रतिभा की मौजूदगी भले ही सीमित थी लेकिन उनके एक्सप्रेशन्स, अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था। देखते ही देखते वह चर्चा का विषय बन गईं और उन्हें नई पहचान मिल गई। इस गाने ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था।

मुस्लिम म्यूजिक कंपोजर ने बर्बाद कर दी प्रतिभा की जिंदगी

–फिल्मी सफर के साथ–साथ प्रतिभा सिन्हा की निजी जिंदगी भी लंबे समय तक खबरों में बनी रही। उस दौर में प्रतिभा सिन्हा का नाम बॉलीवुड के फेमस म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी (ठाीी ग्रं) के साथ जोड़ा गया था। दोनों के रिश्ते को लेकर मीडिया में कई तरह की चचाएं होती थीं।

–बताया जाता है कि प्रतिभा सिन्हा की मां माला सिन्हा को नदीम के साथ उनकी बेटी का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। दरअसल नदीम सैफी पहले से शादीशुदा थे। समय के साथ इस रिश्ते को लेकर कई विवाद और अफवाहें सामने आईं, जिनकी चर्चा फिल्मी गलियारों में लंबे समय तक होती रही। कहा जाता है कि इन घटनाओं का असर प्रतिभा सिन्हा के करियर पर भी पड़ा और उनका ध्यान फिल्मों से धीरे–धीरे

हटने लगा था।

बेटी को बचाने के लिए मां माला सिन्हा ने उठाया बड़ा कदम

–मां माला सिन्हा के मना करने के बावजूद नदीम सैफी और प्रतिभा सिन्हा की लगातार बढ़ती नजदीकियों ने उनके परिवार को परेशान कर रखा था। ऐसे में मां माला सिन्हा ने बड़ा एकदम उठाया और अपनी बेटी को मुंबई से चेन्नई लेकर चली गई थीं ताकि वह नदीम से दूर जा सके। इसके बाद मीडिया में खबर फैली कि प्रतिभा सिन्हा म्यूजिक कंपोजर नदीम सैफी के साथ भाग गई हैं।

–बॉलीवुड ठिकाना की रिपोर्ट के मुताबिक माला सिन्हा ने उस समय इन अफवाहों पर रोक लगाने के लिए बालासाहेब ठाकरे से मदद मांगी थी। कुछ सालों बाद प्रतिभा सिन्हा चेन्नई से वापस मुंबई लौट आई थीं। इस घटना का असर उनके करियर पर पड़ा था जो कि धीर–धीरे बर्बाद हो गया।

शोहरत मिली लेकिन लंबा नहीं चला फिल्मी सफर

प्रतिभा सिन्हा के पास प्रतिभा, खूबसूरती और फिल्मी परिवार का मजबूत आधार था लेकिन इसके बावजूद वह बॉलीवुड में स्थायी मुकाम नहीं बना सकीं। जिस तेजी से उन्हें पहचान मिली थी, उसी तेजी से वह इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर भी हो गईं। साल 2000 के बाद उन्होंने लगभग पूरी तरह फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। इसके बाद वह सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया की नजरों से भी काफी हद तक गायब रहीं।

अब कैसी जिंदगी जी रही हैं प्रतिभा सिन्हा?

–मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार प्रतिभा सिन्हा इन दिनों मुंबई के बांद्रा इलाके में अपनी मां माला सिन्हा के साथ शांत जीवन बिता रही हैं। 57 साल की उम्र हो जाने के बावजूद उन्होंने अब तक शादी नहीं की और लंबे समय से लाइमलाइट से दूर हैं।

–हालांकि प्रतिभा सिन्हा फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं लेकिन 'परदेसी–परदेसी' जैसे यादगार सॉन्ग के कारण आज भी उन्हें बॉलीवुड प्रेमी याद करते हैं। उनका नाम उन एक्ट्रेसेस में लिया जाता है जिन्होंने कम समय में पॉपुलैरिटी तो हासिल की लेकिन उसे लंबे समय तक बरकरार नहीं रख सकीं।

एक सुपरहिट गाने ने प्रतिभा को रातोंरात स्टार बना दिया था

प्रतिभा सिन्हा का फिल्मी सफर उतार–चढ़ाव से भरा रहा। एक सुपरहिट गाने ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया लेकिन सफलता की वह चमक ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। आज वह भले ही ग्लैमर की दुनिया से दूर हों लेकिन 'राजा हिंदुस्तानी' के चर्चित गाने में उनकी झलक अब भी दर्शकों की यादों में ताजा है।

लखनऊ में दिव्यांग छात्रा का सहपाठी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, कार्रवाई न होने के विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ी

(जीएनएस)।

लखनऊ। डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ने सहपाठी पर छल का आरोप लगाया है।

सहपाठी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाने वाली एक दिव्यांग छात्रा शनिवार तड़के सुबह कार्रवाई से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मामले की जानकारी होते ही पारा पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर तक समझाने के बाद छात्रा को लगभग साढ़े सात बजे सुरक्षित नीचे उतारकर थाने ले आई।

दिव्यांग छात्रा का आरोप है कि आरोपित युवक मोहान रोड पर डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का सहपाठी छात्र हैं। पढ़ाई के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। तब युवक ने शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। छात्रा का कहना है कि हम दोनों कुछ समय से लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे

और युवक लगातार शादी का आश्वासन देता रहा।

इसके बाद भी युवक के स्वजन ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। इसके बाद सहपाठी ने छात्रा से दूरी बना ली और शादी से इन्कार कर दिया। इस संबंध में छात्रा ने पारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद कार्रवाई न होने से छात्रा नाराज थी। इसी के विरोध में शनिवार सुबह बुद्धेश्वर चौराहा के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई और आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी।

मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा को समझा बुझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा और आगे की कार्रवाई के लिए थाने ले गई। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है और दबिश दी जा रही है। जल्द से जल्द आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

पारा इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक दिव्यांग छात्रा तड़के सुबह टावर पर चढ़ गई थी। लगभग एक माह पहले छात्रा सहपाठी दिव्यांग छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। छात्रा अब भी उसी सहपाठी छात्र से ही शादी करना चाहती है। लेकिन सहपाठी छात्र शादी के लिए तैयार नहीं है। एक सप्ताह का आश्वासन दिया गया है। छात्र के परिवार का लोगों को बुलाया गया है।

कैरी बैग का 16 रुपये लिया, लखनऊ के लुलु शॉपिंग मॉल पर 4516 रुपये का जुमार्ना; मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप

जौनपुर उपभोक्ता आयोग ने लखनऊ के लुलु हाइपरमार्केट के मैनेजर को कैरी बैग के 16 रुपये अतिरिक्त वसूलने का दोषी ठहराया। आयोग ने उपभोक्ता को 16 रुपये लौटाने के साथ 1,500 रुपये मानसिक उत्पीड़न और 3,000 रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया। 45 दिन में भुगतान न होने पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

(जीएनएस)।

16 रुपये उपभोक्ता से कैरी बैग का अतिरिक्त लेना लखनऊ के लुलु शॉपिंग मॉल के मैनेजर को महंगा पड़ा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जौनपुर के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सदस्य गीता ने परिवादी के परिवाद पर लुलु हाइपर मार्केट लुलु इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ प्रतिष्ठान के मैनेजर को दोषी पाया।

आदेश दिया कि उपभोक्ता को निर्णय के 45 दिन के भीतर कैरी बैग की कीमत 16 रुपये के अलावा मानसिक उत्पीड़न, अनुचित व्यापारिक व्यवहार के लिए 1,500 रुपये व परिवाद व्यय के लिए 3,000 रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें। नियत समय में क्षतिपूर्ति अदा न करने पर 6% वार्षिक ब्याज भी परिवादी को अदा करने के लिए विपक्षी उत्तरदायी होगा।

उमरपुर, रूहट्टा निवासी घनश्याम प्रसाद ओझा ने अधिवक्ता के माध्यम से लुलु हाइपर मार्केट लुलु इंडिया शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ के मैनेजर के खिलाफ परिवाद दाखिल किया, जिसके मुताबिक 1 मार्च 2025 को परिवादी लखनऊ स्थित विपक्षी के प्रतिष्ठान से 669 रुपये का खाने पीने का सामान क्रय किया।

वहां क्रय मूल्य के अतिरिक्त 16 रुपये कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज लिया, जो सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापारिक व्यवहार है। लुलु शॉपिंग मॉल के नियमानुसार ग्राहक कोई कैरी बैग लेकर अंदर नहीं जा सकता, ताकि ग्राहकों से कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क लिया जा सके।

सामानों की खरीदारी के दौरान व खरीदारी के पहले कैरी बैग के अतिरिक्त चार्ज की कोई सूचना वहां नहीं दी गई थी। परिवादी ने खरीदारी संबंधी रसीद इत्यादि दाखिल किया व राष्ट्रीय आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया।

विपक्षी प्रतिष्ठान के अधिवक्ता ने सूचना दिए जाने के फोटोग्राफ एवं कैरी बैग दाखिल किया। जिस पर परिवादी ने तर्क दिया कि लुलु इंडिया शॉपिंग मॉल के मुख्य प्रवेश द्वार पर कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा है। कैरी बैग पर उसकी कीमत भी नहीं लिखी है।

कैरी बैग बेचे जाने पर वह वस्तु की कैटेगरी में आएगा और ग्राहक को कैरी बैग की मुख्य विशेषताओं और उसकी कीमत को पहले ही जानने का अधिकार है। जिससे ग्राहक उसे खरीदने या न खरीदने का विकल्प चुन सके।

फोरम ने आदेश दिया कि सामान चुनने के बाद कैरी बैग की मुख्य विशेषताओं का खुलासा किए बिना विपक्षी कंपनी द्वारा निर्धारित कीमत पर कैरी बैग जबरदस्ती देते हुए उपभोक्ता को शर्मिंदगी और उत्पीड़न की स्थिति में डालते हुए अतिरिक्त लागत का बोझ डालना अनुचित है।

यदि विपक्षी स्वयं को जिम्मेदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का दावा करती है तो उन्हें कैरी बैग मुफ्त में देना चाहिए। विपक्षी अनुचित व्यापारिक व्यवहार का उपयोग कर देश भर में स्थित अपने सभी स्टोरों से भोले-भाले ग्राहकों से भारी मुनाफा कमा रहे हैं यह सेवा में कमी है।

ग्रेटर नोएडा के किसानों का अल्टीमेटम, 4 प्रतिशत आबादी भूखंड न मिलने पर लखनऊ कूच की तैयारी

गौतमबुद्ध नगर के 44 गांवों के किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 6 जुलाई तक 4% अतिरिक्त आबादी भूखंड का मुद्दा सुलझाने का

(जीएनएस)।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के 44 गांवों के किसानों का चार प्रतिशत अतिरिक्त आबादी भूखंड का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। किसानों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि छह जुलाई को सीईओ से वार्ता कराई जाएगी, लेकिन प्राधिकरण द्वारा मामलों के गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

यदि छह जुलाई की बैठक सकारात्मक नहीं रही तो 44 गांवों के किसान चौधरी प्रकाश प्रधान व विनोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में पैदल कूच करेंगे।

पुलिस के आश्वासन पर लखनऊ कूच का निर्धारित कार्यक्रम

प्रकाश प्रधान ने बताया कि आबादी भूखंड की मांग को लेकर पिछले दिनों पुलिस के आश्वासन पर लखनऊ कूच का निर्धारित कार्यक्रम स्थगित कर दिया था। लकनऊ कूच की जानकारी प्राधिकरण सीईओ, जिलाधिकारी व पुलिस आयुक्त को पूर्व में ही दे दी गई थी।

आश्वासान के बाद पुलिस की मौजूदगी में प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव, ओएसडी गिरीश झा, ओएसडी अजय शर्मा, डीजीएम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने सैकड़ों किसानों और पुलिस प्रशासन के सामने आश्वासन दिया कि वह सीईओ एनजी रवि कुमार वार्ता कर चार दिन के भीतर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे।

किसानों ने सर्वसम्मति से छह जुलाई तक का समय दिया

किसानों ने सर्वसम्मति से छह जुलाई तक का समय दे दिया था। यह लड़ाई सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि गौतमबुद्ध नगर के 44 गांवों के किसानों की है। प्राधिकरण हमें वर्षों से केवल आश्वासन दे रहा है। अब और इंतजार नहीं होगा।

विनोद कुमार वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि छह जुलाई तक चार अतिरिक्त आबादी भूखंड की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सैकड़ों पीड़ित किसानों के साथ लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी समस्या बताएंगे।

एलडीए के नियमः लखनऊ में रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंगों के नक्शा पास कराने की शर्तें, आप भी समझिए

उत्तर प्रदेश सरकार की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत बिल्डिंगों को वैध करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया गया है.

(जीएनएस)।

लखनऊः राजधानी लखनऊ में भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. ऐसे में संस्थानों के संचालकों के सामने अपनी बिल्डिंगों को वैध करते हुए नक्शा पास कराने की जरूरत पड़ गई है.

आज हम आपको एलडीए के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर नक्शा पास कराया जा सकता है. उत्तर प्रदेश सरकार की भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के तहत बिल्डिंगों को वैध करने के लिए नियमों में परिवर्तन किया गया है. इनको समझना जरूरी है, क्योंकि इन नियमों के तहत आप अपनी बिल्डिंग का नक्शा एलडीए से पास करा सकते हैं.

ऐसे उपविधि 2025 के अनुसार 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर निर्माण के लिए एलडीए से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है. केवल ऑनलाइन पंजीकरण और 1 रुपये का टोकन शुल्क जमा कर के निर्माण कराया जा सकता है.

500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवनों के नक्शे विश्वास-आधारित ऑनलाइन प्रणाली से स्वतः स्वीकृत हो जाएंगे, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

घर यानी का आवासीय बिल्डिंग में छोटे स्तर पर व्यवसाय किया जा सकता है. नियमों के तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 24 मीटर चौड़ी और अन्य शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़क पर बने आवासीय बिल्डिंग में दुकान, कार्यालय, नर्सरी, होम-स्टे जैसी व्यवसाइक एक्टिविटी की जा सकती है.

इसके साथ ही घर आवासीय भवन के 25 प्रतिशत हिस्से का उपयोग डॉक्टर, वकील या अन्य पेशेवर एक्टिविटी के लिए बिना अलग नक्शा पास कराए किया जा सकता है, हालांकि पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक है.

नियमों के तहत चौड़ी सड़कों पर अधिक निर्माण की अनुमति देते हुए ऋणभार भी बढ़ा दिया है. 45 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर ऋणभार की कोई सीमा नहीं रहेगी.

भवनों की ऊंचाई पर लगा सामान्य प्रतिबंध भी हटा दिया गया है, जिससे ऊंची इमारतों का निर्माण आसान हो गया है. हालांकि एयरपोर्ट और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (अरक) के संरक्षित क्षेत्रों में पहले की तरह विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे.

उपविधि 2025 में ग्रीन-रेटेड भवनों को अतिरिक्त मुफ्त ऋणभार दिया जाएगा. ग्राउंड कवरेज की बाध्यता भी समाप्त हो गई है. सेटबैक नियमों में भी राहत दी जा चुकी है.

होटल, अस्पताल और पेइंग गेस्ट (पीजी) सुविधाओं के लिए अलग से एनओसी लेने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है. वहीं ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार भी कम किया गया है, जिससे छोटे भूखंडों पर भी आवासीय परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं.

18 मीटर चौड़ी सड़क पर शॉपिंग मॉल तथा 9 मीटर चौड़ी सड़क पर क्लीनिक और प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकेंगे। भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्माण के 10वें वर्ष में स्ट्रक्चरल ऑडिट भी अनिवार्य किया गया है.

एलडीए के मुख्य नगर नियोजक के.के. गौतम ने बताया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 लागू होने के बाद भवन का नक्शा पास कराना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है.

उन्होंने कहा कि नए नियमों में पहले की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे लोगों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है.

केके गौतम के अनुसार लोग अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की ऑफीशियल वेबसाइट पर जीकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां आसानी से अपना नक्शा पास करा सकते हैं. अगर आवेदन के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी या अन्य समस्या आती है, तो संबंधित अधिकारी से संपर्क कर समाधान कराया जा सकता है.

सीएम योगी ने रियल-टाइम मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

(जीएनएस)।

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज लखनऊ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा विभिन्न विशेषज्ञों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक मे उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स एवं उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क (UPTEN) की कार्ययोजनाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में चरणबद्ध रूप से कैंसर उपचार सुविधाओं का विकास किया जाए तथा प्रत्येक मंडल में आधुनिक कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि कैंसर की रोकथाम, समयबद्ध स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि दुर्घटना अथवा अन्य गंभीर आपात स्थिति में घायल व्यक्ति को 'गोल्डन ऑवर' के भीतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, ट्रॉमा केंद्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल रेफरल प्रणाली विकसित करने तथा एंबुलेंस, बेड उपलब्धता एवं उपचार सुविधाओं की

रियल-टाइम मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों एवं एक्सप्रेस-वे पर त्वरित आपात चिकित्सा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को केवल उपचार केंद्रित न रखकर रोकथाम, शीघ्र पहचान, गुणवत्तापूर्ण उपचार, पुनर्वास, अनुसंधान एवं तकनीक

आधारित समन्वित स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं पैरामेडिकल कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आधुनिक चिकित्सा के साथ पुनर्वास, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग, योग एवं आयुष आधारित समन्वित सेवाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

रालोद को रास आ रहा बीजेपी संग गठबंधन, योगी की शान में कसीदे पढ़ रहे जयंत के नेता

(जीएनएस)।

मेरठ, यूपी में जाट बेल्ट की पार्टी कहे जाने वाली रालोद राज्य में करीब-करीब हर बड़ी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में रालोद किसके मिलकर चुनाव लड़ेगी, यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है लेकिन फिलहाल हालातों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि अजित सिंह के वारिस केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को बीजेपी का साथ बेहद पसंद आ रहा है।

बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी रालोद नेताओं की करीबी बढ़ी है। इसके कई मजबूत संकेत साफ दिख रहे है। जयंत चौधरी पर बढ़ती निर्भरता का ही नतीजा है कि जाट बेल्ट वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष जाट के बजाय गुर्जर बिरादरी के अपने पुराने साधारण से कार्यकर्ता पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर को बनाया है।

रालोद कोटे से योगी सरकार में काबिना मंत्री और दलित चेहरे अनिल कुमार (मुरादाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री भी) ने जनसत्ता से बातचीत में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व, कार्यप्रणाली और किसान-गांव समर्थक नीतियों के तेजी से क्रियान्वयन को लेकर उनके जमकर कसीदे पढ़े। उन का कहना है कि रालोद को बीजेपी में और उन्हें योगी सरकार में भरपूर तव्वजो मिल रही है।

इससे पहले भी मुरादाबाद में अनिल कुमार योगी आदित्यनाथ के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग में मौजूद थे। अनिल कुमार ने कहा कि योगी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावे, दान-चंदे की लूट-चोरी की शर्मनाक घटना का योगी की छवि एवं सरकार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है।

अनिल कुमार ने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव में रालोद नेता सभी 403 सीटों पर एनडीए के पक्ष में प्रचार और काम करेंगे। हाल ही में वरिष्ठ नेता केसी त्यागी की अध्यक्षता में गठित संसदीय दल में खुद को एवं सांसद चंदन चौहान को नहीं रखे जाने पर अनिल कुमार के कहा कि शीर्ष स्तर पर तय हुआ है कि चुनाव लड़ने वाले नेता इसमें नहीं रखे जाएंगे।

उन्होंने दावा किया कि वह पुरकाजी से चुनाव लड़ेंगे और जयंत चौधरी यशिका चौहान को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं, इसलिए चंदन चौहान को भी संसदीय दल में नहीं रखा गया है।

यूपी चुनाव 2027 के मिशन पर नितिन नवीन, रोड शो में मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी के क्या हैं मायने?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मिशन यूपी 2027 पर निकल गए हैं. पहले दिन जहां अमौसी एयरपोर्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उनका भव्य स्वागत किया. वहीं रोड शो के दौरान तलवार भी भांजी. बुर्का पहनी महिलाओं ने स्वागत किया और टोपी पहने मुस्लिम पुरुष भी फूल बरसाये.

(जीएनएस)।

लखनऊ. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मिशन यूपी 2027 शुरू हो गया. पहले दिन शनिवार को नितिन नवीन ने लखनऊ में रोड शो किया. एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक 18 किलोमीटर लंबा यह रोड शो 11:20 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:55 बजे समाप्त हुआ. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ नितिन नवीन की केमिस्ट्री काफ जच रही थी. पूरे रास्ते कार्यकताओं ने फूल-मालाओं से उनका स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की. रोड शो के दौरान नितिन नवीन ने समर्थकों का अभिवादन करते हुए तलवार भी लहराई. इस दौरान बड़ी संख्या में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाएं और टोपी पहने मुस्लिम पुरुष भी रोड शो में शामिल हुए. इस दौरान बीजेपी कार्यकताओं ने बुलडोजर की मदद से 25 फीट की विशालकाय माला भी पहनाई.

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शनिवार को अपने पहले दो दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे. नई प्रदेश टीम के गठन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह पहला यूपी दौरा है, जिसे बेहद खास और रणनीतिक माना जा रहा है. शनिवार सुबह से लेकर देर रात तक नितिन नवीन की व्यस्त दिनचर्या, मैराथन बैठकों का दौर और धार्मिक अनुष्ठानों ने साफ कर दिया कि भाजपा उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.

शनिवार सुबह करीब 11:00 बजे जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का अमौसी एयरपोर्ट पर उतरा, तो वहां का नजारा बेहद उत्साहजनक था. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने गुलदस्ता भेंट कर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार

स्वागत किया. उनके साथ दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे.

एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही नितिन नवीन का काफिला एक विशाल रोड शो में तब्दील हो गया. एयरपोर्ट से प्रदेश भाजपा मुख्यालय की दूरी तय करने के दौरान आलमबाग, टी.एन. चतुवेर्दी चौराहा, चारबाग, दीनदयाल स्मृतिका, महाराणा प्रताप चौराहा और बलिंगटन चौराहा जैसी करीब 40 जगहों पर कार्यकताओं ने उन पर फूलों की बारिश की. विभिन्न सामाजिक, व्यापारिक और युवा संगठनों ने ढोल-नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में पार्टी के राज्य पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्षों, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण और हाई-प्रोफाइल संगठनात्मक बैठक की. बैठक में नितिन नवीन ने साफ संदेश दिया कि 2027 की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी. सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक जाकर सरकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने और सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने का निर्देश दिया.

संगठनात्मक बैठकों के पहले दौर के बाद शाम ठीक 4:00 बजे नितिन नवीन पुराने हैदराबाद स्थित लखनऊ के प्रसिद्ध श्री हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे. उनके साथ सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विधि-विधान से बजरंगबली की पूजा-अर्चना की और आरती उतारी. उन्होंने उत्तर प्रदेश की सुख, समृद्धि और आगामी राजनीतिक लड़ाइयों में पार्टी की विजय के लिए संकटमोचन से आशीर्वाद मांगा.

नितिन नवीन के इस दौरे से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी मशीनरी को पूरी तरह से री-एक्टिवेट कर चुकी है. रविवार को होने वाली एनडीए सहयोगियों अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा और रालोद के नेताओं के साथ बैठक से पहले ही नितिन नवीन ने यह साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव पूरी तरह आपसी तालमेल के साथ लड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों उपमुख्यमंत्रियों के साथ मंच और बैठकें साझा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश भाजपा में ऑल इज वेल है और पूरी पार्टी एक कमान के नीचे काम कर रही है. दौरे के दूसरे दिन होने वाले शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन और एक बूथ अध्यक्ष के घर चाय पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए शीर्ष नेतृत्व सीधे अंतिम पायदान के कार्यकर्ता को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहा है.

किसानों की बल्ले-बल्लेः YEIDA 5100 किसानों को जल्द देगा 7 प्रतिशत आबादी भूखंड, सीएम योगी सौंपेंगे आवंटन पत्र

(जीएनएस)।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण किसानों को जल्द सात प्रतिशत आबादी भूखंड के आवंटन पत्र जारी होंगे। यीडा अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से किसानों को आवंटन पत्र दिलाने की तैयारी में जुटे हैं। पहले चरण में 5100 किसानों को आवंटन पत्र सौंपने की तैयारी है।

यमुना प्राधिकरण औद्योगिक विकास परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण या सहमति के जरिये क्रय करता है। इसके एवज में किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड आवंटित होते हैं, लेकिन अधिकतर गांवों के किसानों को लंबे समय से भूखंडों का आवंटन नहीं हुआ है।

किसान संगठन इसके लिए प्राधिकरण से लगातार मांग करते आ रहे हैं। संगठनों की मांग पर प्राधिकरण ने किसानों को भूखंड का आरक्षण पत्र जारी किए थे, लेकिन अब 5100

किसानों को आवंटन पत्र भी जारी करने की तैयारी है। आवंटन पत्र प्राधिकरण तब ही जारी करता है जब भूखंड को विकसित कर दिया जाता है।

प्राधिकरण अब तक 11211 किसानों में से 7035 को आरक्षण पत्र सौंप चुका है। 4176 किसानों के भूखंड नियोजित भी हो चुके हैं। प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जल्द ही 5100 भूखंडों के आवंटन पत्र किसानों को सौंपे जाएंगे। शेष भूखंडों का भी तेजी से नियोजन किया जा रहा है।

इन गांवों के किसानों को दिए जाएंगे भूखंड

जिन गांवों के किसानों को सात प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाएंगे उनमें गुनपुरा, मथुरापुर, मूंजखेड़ा, औरंगपुर, बेला कला, सलारपुर, मुस्तफाबाद, रामपुर बांगर, चांदपुर, मिजार्पुर, रुस्तमपुर, पारसौल, उस्मानपुर, डूंगरपुर रीलका, आच्छेपुर, पचोकरा, अच्छेजा बुजुर्ग, निलौनी शाहपुर, धनौरी, कादरपुर, रौनीजा, तिरथली, वीरमपुर आदि गांव शामिल हैं।

इसके अलावा दनकौर, अट्टा गुजरान, जगनपुर के एसआइटी जांच के प्रकरणों को छोड़कर अन्य किसानों को भूखंड दिए जाएंगे।